

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2022

प्रलिस के लयः

वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2022, UNEP, CITES ।

मेन्स के लयः

जैव वविधता और वन्यजीव का महत्त्व, वन्यजीव का (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2022 का महत्त्व ।

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में राज्यसभा ने वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2022 पारति कया, जो वन्यजीवों और वनस्पतयों की लुप्तपराय प्रजातयों पर अंतरराष्टरीय व्यापार सममेलन (Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) के तहत भारत के दायतयों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है ।

वधियक का उद्देश्यः

- लुप्तपराय प्रजातयों का संरक्षण: वधियक अवैध वन्यजीव व्यापार के लयः सजा बढ़ाने का प्रयास करता है ।
- संरक्षति क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन: यह स्थानीय समुदायों द्वारा पशुओं के चरने या आवाजाही और पीने एवं घरेलू जल के वास्तवकि उपयोग जैसी कुछ अनुमत गतवधियों के लयः अनुमति प्रदान करता है ।
- वन भूमिका संरक्षण: संबद्ध वनक्षेत्र में सदयों से रह रहे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को समान रूप से शामिल करना ।

प्रस्तावति संशोधन

- इस संशोधन ने CITES के तहत परशिषिट में सूचीबद्ध प्रजातयों के लयः एक नया कार्यक्रम प्रस्तावति कया ।
- ऐसी शक्तयों और करतव्यों का प्रयोग करने एवं स्थायी समति का गठन करने के लयः धारा 6 में संशोधन कया गया है जो इसेराज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजति कया जा सकता है ।
- अधनियम की धारा 43 में संशोधन कया गया जसिमें 'धार्मकि या कसिी अन्य उद्देश्य' के लयः हाथयों के उपयोग की अनुमति दी गई है ।
- केंद्र सरकार को एक प्रबंधन प्राधकिरण नयिकृत करने में सक्षम बनाने के लयः धारा 49E को जोड़ा गया है ।
- केंद्र सरकार को एक वैज्ञानकि प्राधकिरण नयिकृत करने की अनुमति देना जो व्यापार कयि जाने वाले नमूनों के अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधति मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करे ।
- वधियक केंद्र सरकार को वदिशी प्रजातयों के आक्रामक पौधे या पशु के आयात, व्यापार या नयित्रण को वनियमति करने और रोकने का भी अधिकार देता है ।
- वधियक अधनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लयः नरिधारति दंड को भी बढ़ाता है ।
 - 'सामान्य उल्लंघन' के लयः अधिकतम जुर्माना 25,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दया गया है ।
 - वशिष रूप से संरक्षति पशुओं के मामले में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दया गया है ।

वधियक से जुडी चतिाँ:

- वाक्यांश "कोई अन्य उद्देश्य" अस्पष्ट है और हाथयों के वाणज्यकि व्यापार को प्रोत्साहति करने की क्षमता रखता है ।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र नयिम आदि से संबंधति कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दया गया है ।
- संसदीय स्थायी समति द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार वधियक की तीनों अनुसूचयों में सूचीबद्ध प्रजातयों अधूरी हैं ।
- वैज्ञानकि, वनस्पतशास्त्री, जीववज्जानी संख्या में कम हैं और वन्यजीवों की सभी मौजूदा प्रजातयों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रया में तेज़ी लाने के लयः उन्हें अधिक से अधिक शामिल करने की आवश्यकता है ।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन एवं वनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- यह अधिनियम सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और नगिरानी प्राप्त उन **पौधों और पशुओं की अनुसूची** को भी सूचीबद्ध करता है।

CITES:

- CITES एक **अंतरराष्ट्रीय समझौता** है जिसका राष्ट्र और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं।
- वर्ष 1963 में **अंतरराष्ट्रीय प्रकृत संरक्षण संघ** (International Union for Conservation of Nature- IUCN) के सदस्य देशों की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप CITES का मसौदा तैयार किया गया था।
- CITES जुलाई 1975 में लागू हुआ था।
- CITES सचिवालय जनिवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** द्वारा प्रशासित है।
- भारत CITES का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

वन्यजीव संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976**, द्वारा वन और जंगली पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।
- संवैधानिक अनुच्छेद 51A(जी) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।
- राज्य नीतिके नदिशक सिद्धांतों में **अनुच्छेद 48 ए**, के तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा और वकिसति करने तथा देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

आगे की राह:

- वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कानून का सख्ती से पालन आवश्यक है।
- अचल संपत्ति में शामिल व्यवसायों और नगिर्मों को अपनी धन और बल शक्तिको संतुलित करने के लिये कानून का सख्ती से पालन करना चाहिये।
 - कुछ नगिर्मों के लाभ के लिये नकिोबार के जंगलों को पूरी तरह से उजाड़ा व नष्ट किया जा रहा है।
 - अतः मुख्य रूप से, वन्यजीवों पर वास्तव में मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि नगिर्मों द्वारा हमला किया जा रहा है।
- केवल नयिर्मों और तकनीकी की समझ ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आदवािसी समुदायों को भी अपने अधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. यदाकिसी विशेष पादप प्रजातिको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका अर्थ क्या है? (2020)

- (a) उस पौधे को उगाने के लिये लाइसेंस की जरूरत होती है।
- (b) ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है।
- (c) यह एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल का पौधा है।
- (d) ऐसा पौधा आक्रामक और पारिस्थितिकी तंत्र के लिये हानिकारक है।

उत्तर: (a)

स्रोत: द हिंदू